दै. स्वदेश, भोपाल
30 AUG 2012

संपादकीय

शिवराज सरकार का विकास मॉडल

दिल्ली में आयोजित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन इन राज्यों की उपलब्धियों का प्रदर्शन भर ही नहीं था। यह सम्मेलन दरअसल जनता के प्रति भाजपा की जिम्मेदारी के अहसास का परिचायक था। इन सभी राज्यों में प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका अदा कर रही कांग्रेस की अयोग्यता और अक्षमता के कारण भाजपा पर जो अतिरिक्त दायित्व आ गया है, यह सम्मेलन उसी के निर्वहन की रूपरेखा तैयार करने के लिए आयोजित किया गया था। इन तमाम राज्यों में पार्टी ने जनहित के सुशासन का जो रोड मेप पार्टी ने तैयार किया था, भाजपा सरकारों ने उसको अमलीजामा पहनाने का काम इतनी खूबी से किया है कि कांग्रेस का विरोध पूरी तरह से भौंथरा हो गया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अपनी संगठनात्मक कमजोरियों और जनता पर कमजोर पकड़ के चलते विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं किया है। जिसकी वजह से जनता कांग्रेस से निराश और हताश हो चुकी है। कांग्रेस की इस नाकाबिलियत के कारण स्वाभाविक रूप से भाजपा पर यह महती जिम्मेदारी आ पड़ी है कि विपक्ष के नाम पर निर्मित इस महाशून्य से जनता में उपजी निराशा को दूर करे और अपनी सरकारों की उपलब्धियों के जरिये उसे यह अहसास दिलाए कि उन्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भाजपा सरकारें उनकी खुशहाली की नई इबारत लिखने में सक्षम हैं।

सम्मेलन में भाजपा सरकारों की उपलब्धियों का जो चित्र उभर कर सामने आया है, वह इस दृष्टि से काफी उत्साहवर्धक है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार के विकास कार्यों के बारे में काफी कुछ कहा सुना जा चुका है लेकिन भाजपा मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में शिवराज सिंह ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जो चित्र प्रस्तुत किया उसने सबको अभिभूत कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपने भाषण में यह साबित कर दिया कि केंद्र सरकार की तुलना में मध्यप्रदेश सरकार की उपलब्धियां कहीं ज्यादा चमकदार है। इसका प्रमाण यही है कि केंद्र की कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के नेतृत्व में देश में कुल 6.5 प्रतिशत विकास दर हासिल जा सकी है। इसकी तुलना में मध्यप्रदेश में प्राप्त की गई 11.98 प्रतिशत की विकास दर इसी तथ्य को दर्शाती है। इसी तरह केंद्र द्वारा प्राप्त 7.8 प्रतिशत की तुलना में मध्यप्रदेश ने 10.2 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद भी हासिल किया है। राजस्व वसूली के मामले में भी मध्यप्देश का आंकड़ा केंद्र की अपेक्षा लगभग डेढ़ प्रतिशत ज्यादा है। केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार की कालिख से पुते चेहरे को शिवराज सिंह ने लोकसेवा गारंटी अधिनियम बनाकर आइना दिखा दिया है। एक ओर जहां शिवराज सरकार ने विकेंदीकृत जिला योजना तथा हर वर्ग के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पंचायतों का आयोजन कर जनहित के प्रति अपने संकल्प का इजहार किया है, है वहीं बालिका बचाओ सहित विभिन्न योजनाओं के जरिये महिलाओं को न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मुख्यमंत्री की पहल ने आधी आबादी के प्रति उनके जिम्मेदारीपूर्ण नजरिये को प्रदर्शित किया है। शिवराज सरकार की इन्हीं उपलब्धियों से पार्टी को यह उम्मीद बंधी है कि वे पुन: जनता का विश्वास हासिल करने में कामयाब होंगे।

केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार की कालिख से पुते चेहरे को शिवराज सिंह ने लोकसेवा गारंटी अधिनियम बनाकर आइना दिखा दिया है। शिवराज सरकार ने अपने कार्यों के जरिये जनहित के प्रति अपने संकल्प का ही प्रदर्शन किया है। शिवराज सरकार की इन्हीं उपलब्धियों से पार्टी को यह उम्मीद बंधी है कि वे पुन: जनता का विश्वास हासिल करने में कामयाब होंगे।